शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

कटौती के साइड इफेक्ट : स्थितियां नहीं सुधरी तो आगे भी नुकसान तय

कर्मचारियों की कर्जदार बनी सरकार, 38 हजार करोड़ रुपए डूबने का खतरा

एक्सक्लूसिव

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. कोरोना संकट की आड़ में प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की जेब पर ऐसी कैंची चलाई कि वह कर्मचारियों की कर्जदार बन गई। यह करीब 38 हजार करोड़ रुपए का मामला है। इसका सीधा नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। खजाने की माली हालत खराब होने के कारण प्रदेश सरकार भी केंद्र के भरोसे है।

कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना संकटकाल में वे सरकार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय उनकी जेब पर ही कैंची चला दी। पहले कर्मचारियों का एरियर रोका, फिर बढ़े हुए डीए का भुगान देने से रोक लगा दी। इससे कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके पीछे सरकार के खजाने की माली हालत खराब होने का तर्क दिया गया।

कर्मचारी कोरोना काल में भी काम कर रहे हैं।

एक साल तक डीए नहीं बढ़ेगा

सरकार ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए कर्मचारियों को अगले एक साल तक डीए देने पर रोक लगा दी है। अब उन्हें जुलाई 2021 से डीए देने की बात कही जा रही है।

ऐसे समझें कर्ज का हिसाब

- **सातवें** वेतनमान की एरियर की किस्त - 1500 करोड़ रुपए
- **चार माह** का डीए मिलना था - 250 करोड़ रुपए
- **पांच माह** का डीए रोका - 1250 करोड़ रुपए
- **रिटायर हो** रहे कर्मचारियों के भुगतान रोके - 35000 करोड़ रुपए

ऐसे हुआ एरियर और डीए का नुकसान

राज्य कर्मचारियों को जनवरी 2016 में सातवां वेतनमान दिया था, लेकिन इसका नकद भुगतान जुलाई 2017 से किया। उन्हें 18 माह का एरियर तीन किस्तों में देना था तीन किस्त प्रतिवर्ष मई माह में मिलना थी। दो किस्तें मिली, लेकिन मई 2020 की तीसरी किस्त रोक ली गई। कुछ ऐसी ही स्थिति डीए के मामले में बनी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पांच प्रतिशत डीए देने के आदेश जारी हो गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस डीए को स्थगित कर दिया। इसी प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों के समान चार प्रतिशत डीए भी जनवरी माह से मिलना था, लेकिन यह भी नहीं मिला। इस तरह नौ प्रतिशत डीए का नुकसान हुआ।

पेंशनर्स का 32 माह का एरियर डूबा

सातवें वेतनमान की बात करें तो भाजपा शासनकाल में राज्य कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया गया। पेंशनर्स को भी यही लाभ मिला, लेकिन उन्हें छठवें वेतनमान का 32 माह का एरियर नहीं दिया गया। तीन हजार करोड़ रुपए का यह एरियर उनका डूबत खाते का है। पेंशनर्स इसे भूल चुके हैं।

रिटायर कर्मचारियों का भुगतान अटका

पिछले छह माह में रिटायर हुए कर्मचारियों की बात करें तो अधिकतर के भुगतान अटके हैं। मार्च के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को सिर्फ रिटायरमेंट का आदेश मिला, लेकिन उनके किसी भी प्रकार के भुगतान नहीं हुए। इनमें उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी सहित अन्य भुगतान शामिल हैं। यह राशि 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक की है।

> राज्य कर्मचारी सरकार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके भुगतान पर ही रोक लगा रही है। यह उचित नहीं है। कर्मचारी महंगाई से जूझ रहे हैं, अब भुगतानों पर रोक लगने का सीधा असर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द उनके भुगतान किए जाएं।
>
> **लक्ष्मीनारायण शर्मा,** महामंत्री, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ

9 जून से 16 जून तक होंगी 12वीं की शेष परीक्षाएं

भोपाल। माशिमं ने बारहवीं का टाइम टेबल नए सिरे से जारी किया है। अब कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक आयोजित होंगी। पहले परीक्षाएं 9 जून से 15 जून तक आयोजित थी। 9 जून को सुबह 9 बजे केमेस्ट्री ,दोपहर 2 बजे भूगोल, 10 जून को सुबह बुक कीपिंग एवं अकाउंटेंसी, दोपहर 2 बजे प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, 11 जून सुबह 9 बजे बॉयोलॉजी, 12 जून सुबह 9 बजे व्यवसायिक अर्थशास्त्र, दोपहर 2 बजे एनिमल हसबेंडरी मिल्कट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एंड फिशरीज का पेपर होगा।

बोर्ड ने 12वीं के टाइम टेबल में किया बदलाव

भोपाल. एमपी बोर्ड ने 12वीं के बचे प्रश्नपत्रों की तारीखों में बदलाव किया है। परीक्षाएं 9-16 जून तक होंगी। 9 जून को सुबह हायर मैथेमेटिक्स की जगह केमिस्ट्री और दोपहर में भूगोल का पेपर होगा। हायर मैथेमेटिक्स का पेपर 15 जून को सुबह 9 बजे से होगा। अर्थशास्त्र और क्रॉप प्रोडक्शन एंड हर्टिकल्चर 16 जून को होगा।

माशिमं: स्कूल शिक्षा विभाग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

स्टूडेंट्स और स्टाफ को एक घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिलेगा प्रवेश

9 जून से शुरू होने वाली 12वीं के शेष पेपरों की परीक्षा को लेकर लगभग तैयारियां पूरी

हरिभूमि न्यूज ▸▸ भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने 9 जून से शुरू होने वाली 12वीं के शेष पेपरों की परीक्षा को लेकर लगभग पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के साथ ही क्वारेंटाइन एरिया के बच्चों को जिला प्रशासन की मदद से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्टूडेंट्स और ड्यूटी में लगाए गए स्टाफ को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। मास्क सभी के लिए अनिवार्य होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को बोर्ड परीक्षाओं को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) की गई। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी व एमपीबीएसई के सचिव अनिल सुचारी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने डीईओ द्वारा की गई डिमांड को भी सुना। इसमें सबसे बड़ी समस्या कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी और उनमें बने एग्जाम सेंटरों को लेकर सामने आई है। दूसरी समस्या सार्वजनिक परिवहन नहीं शुरू होने की स्थिति में स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटरों तक पहुंचाना भी एक चुनौती है। वीसी में डीईओ ने एग्जाम के दौरान आने वाली समस्याएं अधिकारियों ने समक्ष रखी, वहीं कंटेनमेंट क्षेत्र में आने वाले एग्जाम सेंटरों में बदलाव का प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग ने आला अधिकारियों के समक्ष रखा गया।

खास बातें

- क्वारेंटाइन एरिया के बच्चों को जिला प्रशासन पहुंचाएगा परीक्षा केंद्र
- सार्वजनिक परिवहन शुरू न होना भी बच्चों के सामने है चुनौती

जो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन्हें पूरक परीक्षार्थियों के साथ दिलाएंगे परीक्षा

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कोरोना संक्रमण को देखते हुए एग्जाम से पहले व बाद में सभी एग्जाम सेंटरों को सेनिटाइज किया जाएगा। यदि सेंटर में स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो उसका नया एग्जाम सेंटर बनाया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स क्वारेंटाइन होने के चलते परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन्हें पूरक परीक्षा वाले विद्यार्थियों के साथ बिठाकर परीक्षा दिलाई जाएगी। हालांकि इन बच्चों को पूरक परीक्षार्थियों में नहीं गिना जाएगा।

12वीं के शेष पेपरों का नया टाइम टेबल

- 9 जून : सुबह 9 बजे से - केमिस्ट्री
  दोपहर 2 बजे से - भूगोल
- 10 जून : सुबह 9 बजे से - बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी
  दोपहर 2 बजे से - प्रथम प्रश्न-पत्र व्होकेशनल कोर्स
- 11 जून : सुबह 9 बजे से - बायलॉजी
- 12 जून : सुबह 9 बजे से - व्यावसायिक अर्थशास्त्र
  दोपहर 2 बजे से - एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर एग्रीकल्चर
- 13 जून : सुबह 9 बजे से - राजनीति शास्त्र
  दोपहर 2 बजे से - शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, स्टिल लाइफ एण्ड डिजाइन, द्वितीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स
- 15 जून : सुबह 9 बजे से - हायर मैथमेटिक्स
  दोपहर 2 बजे से - विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, तृतीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स
- 16 जून : सुबह 9 बजे से - अर्थशास्त्र
  दोपहर 2 बजे से - क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर

एनसीईआरटी : स्कूलों को दोबारा खोलने की रणनीति तैयार करने में जुटा मानव संसाधन विकास मंत्रालय

तीन माह और स्कूल नहीं जाएंगे 5वीं तक के छात्र, छठवीं से खुलेंगे स्कूल

कक्षा को बैच में बांटा जाएगा, छह फुट की दूरी पर बैठेंगे छात्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

नई दिल्ली. केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। पहले चरण में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़ी दूसरी बातों का बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च (एनसीईआरटी) के साथ मिलकर स्कूलों को खोलने के बारे में गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार कक्षा एक से पांच के छात्र जिनकी उम्र 6 से 10 वर्ष होती है, उन्हें अगले तीन महीनों तक स्कूल भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है।

सूत्रों के अनुसार सभी सीनियर क्लासों के छात्रों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। ये लोग कुछ दिनों तक बैच में आएंगे, जिससे स्कूल प्रबंधन को उन्हें नई बैठक व्यवस्था और नियमों के बारे में बताने के लिए समय मिल सके। बैठक व्यवस्थाएं इस तरह की होंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। मतलब कि दो छात्रों के बीच की दूरी छह फुट हो। इसके अलावा कक्षा के सभी छात्रों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा और कक्षा को बैच में बांटा जाएगा।

एक दिन छोड़कर बुलाएंगे बैच को

हर कक्षा या सेक्शन को 15 से 20 विद्यार्थियों में बांटा जाएगा। एक कक्षा के हर बैच को एक दिन छोड़कर बुलाया जाएगा। अधिकारी बताते हैं कि स्कूल में जिस बैच की छुट्टी होगी उसे होमवर्क दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न बैचों के प्रवेश और निकास के समय में काफी अंतर होगा, इसलिए स्कूल प्रबंधन के पास कक्षाओं और सतहों को साफ करने के लिए पर्याप्त समय होगा।

कैंटीन बंद, मास्क अनिवार्य

गाइडलाइंस में इस बात को भी शामिल करने की संभावना है कि सभी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शुरुआत में स्कूल के अंदर की कैंटीन को नहीं खोला जाएगा। छात्रों से कहा जाएगा कि वे टिफिन घर से लेकर आएं। कुछ महीनों तक सुबह के समय होने वाली प्रार्थना (असेंबली) भी बंद रखी जा सकती है।

पैरेंट्स नहीं जा पाएंगे कैंपस में

मां-पिता को स्कूल कैंपस के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों के आने और जाने के लिए अलग-अलग गेट होंगे। स्कूल में सभी जगह को सैनेटाइज किया जाएगा। दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना संकट के कारण स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं।

स्कूल स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम से बचाने जारी हुई 98 पेज की हैंडबुक

सिटी रिपोर्टर, जबलपुर

साइबर सिक्योरिटी के लिए स्टूडेंट्स को अवेयर करने के मकसद से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक जारी की है। 98 पेज की यह बुक क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें साइबर सेफ्टी के टिप्स दिए गए हैं। बुक में फिजिकल हरासमेंट, साइबर क्राइम, धोखाधड़ी, सामाजिक बहिष्कार, धमकी, मानहानि, इमोशनल हरासमेंट से जुड़ी कई तरहों की जानकारियाँ दी गई हैं। स्टूडेंट्स इस हैंड बुक को cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/Cyber_Safety_Manual.pdf लिंक पर विजिट कर डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रिंसिपल हैंडबुक भी- सीबीएसई ने स्कूल प्रिंसिपल को बोर्ड की प्रणालियों और टीचर्स को जरूरी स्किल्स से वाकिफ कराने प्रिंसिपल हैंडबुक और 21 सेंचुरी स्किल्स हैंडबुक भी जारी की है।पी-2

जेईई : 31 तक कराएँ एप्लिकेशन में करेक्शन

जेईई मेन्स 2020 की एप्लिकेशन प्रोसेस पूरी हो गई है। एनटीए ने स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। लॉकडाउन की वजह से जेईई मेन्स 2020 को स्थगित कर दिया था। अब जेईई मेन्स का आयोजन 18, 20, 21 व 22 जुलाई 2020 को होगा। वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 31 मई को शाम के 5 बजे तक किया जा सकता है।पी-3

ऑनलाइन पढ़ाई की होगी मॉनिटरिंग

लापरवाह शिक्षकों की सूची बनाने के दिए गए आदेश

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में एहतियात के तौर पर लॉकडाउन जारी है। शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। विभाग डीजीलैप, व्हाट्सअप सहित दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामाग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के बाद अब इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग कराने की तैयारी कर रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेशभर के संकुल समन्वयक और जन शिक्षा केंद्र प्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि विभाग द्वारा समय-समय पर शैक्षणिक सामाग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रचार-प्रसार पर दिया जाए जोर

स्टूडेंट्स को डीजीलैप संबंधी जानकारी देने के साथ ही इसके प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाए। रोजाना कम से कम दो स्टूडेंट्स, दो अभिभावक-शिक्षकों से फीडबैक लिया जाए। बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को पुरूष्कृत करने के लिए जानकारी तैयार की जाए।

परीक्षा देने के पहले छात्रों की होगी स्क्रीनिंग, क्वारेंटाइन वाले सेंटर बदले जाएंगे

माशिमं ने 12वीं की परीक्षा के लिए जारी की गाइड लाइन

24 हजार छात्र होंगे शामिल, 9 से 16 जून तक चलेंगी परीक्षाएं

जागरण, रीवा

माशिमं ने 12 वीं बोर्ड की शेष रह गए प्रश्न पत्रों की परीक्षा आयोजित करने समय सारणी जारी कर दी है। शेष प्रश्न पत्रों के आयोजन के साथ ही गाइड लाइन भी जारी किया गया है। सभी परीक्षा केन्द्रों में छात्रों की स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं जो परीक्षा केन्द्र क्वारेंटाइन सेंटर बने हैं, उन्हें भी बदला जाएगा। परीक्षा के पहले कक्षाओं को सेनेटाइज कराया जाएगा। हाथ धोने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं।

ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के कारण 20 मार्च के बाद ही बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। 10 वीं बोर्ड की परीक्षा तो अब नहीं होगी, लेकिन 12 वीं की टाइम टेबिल जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12 वीं की परीक्षा 9 जून से शुरू होकर 15 जून तक चलेंगी। इस दौरान रीवा के रेग्युलर और प्राइवेट करीब 24 हजार 131 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा की टाइम टेबिल जारी होने के साथ ही माशिमं ने गाइड लाइन भी जारी कर दी है। परीक्षा हाल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को नाक मुंह पर नकाब या कपड़े से ढ़क कर रखना होगा। फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन करना होगा। अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरते जाने सावधानियों के बारे में जानकारी देना होगा । साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे बीमार ना हो।

यह सारी व्यवस्थाएं सेंटर में करनी होंगी : परीक्षा के पूर्व माशिमं ने प्रशासन को कोरोना से बचने कई इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में यदि कोई परीक्षा केन्द्र निर्धारित है अथवा किसी परीक्षा केन्द्र को नोवेल कोरोना के संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है तो ऐसे क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों को कलेक्टर परिवर्तित कर 28 मई तक सूचना देंगे। परीक्षा केन्द्रों को सेनेटाइज कराया जाए। सेनेटाइजर और साबुन पानी की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केन्द्र में छात्रों को नाक, मुंह को ढंक कर आना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी केन्द्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में दिक्कतें होती है तो उसका उपकेन्द्र बनाकर परीक्षा कराई जाएग। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जो छात्र एक जिले से दूसरे जिले में विस्थापित हुए हैं, उनसे 28 मई तक आनलाइन आवेदन लेने के भी निर्देश हैं। सभी परीक्षा केन्द्रों में थर्मल स्क्रीनिंग के भी आदेश जारी किए गए हैं।

किस दिन कौन सा प्रश्नपत्र : मंगलवार 9 जून को सुबह 9 से 12 बजे तक हायर मेथेमेटिक्स व दोपहर 2 से 5 बजे तक भूगोल का प्रश्न पत्र होगा। बुधवार 10 जून को सुबह बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी और दूसरी पाली में क्रूप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर और प्रथम प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स, गुरूवार 11 जून को बायलॉजी और अर्थशास्त्र, शुक्रवार को व्यावसायिक अर्थशास्त्र और एनिमल हस्बेण्ड्री मिल्कट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एंड फिसरीज, शनिवार को सुबह राजनीति शास्त्र और दूसरी पाली में शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन , द्वितीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स, सोमवार 15 मार्च को सुबह केमिस्ट्री और दूसरी पाली में विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास एवं तृतीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

दिव्यांग छात्रों की संशोधित समय सारिणी

दिव्यांग छात्रों की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। मंगलवार 9 जून को हायर मेथमेटिक्स, भूगोल का प्रश्न पत्र होगा। बुधवार 10 जून को बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी, कॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, गुरुवार को बायलॉजी, अर्थशास्त्र, शुकवार 12 जून को व्यावसायिक अर्थशास्त्र, एनिमल हास्बेण्ड्री, शनिवार को राजनीति शास्त्र, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, शरीर रचना किया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, सोमवार 16 जून को केमिस्ट्री, भारतीय कला का इतिहास, समाज शास्त्र, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, इनवायरमेंट एजुकेशन के प्रश्नपत्र होंगे।

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 मई तक : माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हई स्कूल तथा हयर सेकण्डरी परीक्षाए व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा तथा अंध, मूक बधिर हयर सेकण्डरी परीक्षा के शेष प्रश्न पत्र 9 जून से आयोजित हो रहे हैं। लॉकडाउन तथा अन्य कारणों से यदि कोई परीक्षार्थी अपने परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन चाहता है तो उचित कारण के साथ 28 मई को ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन एमपी ऑनलाइन, एजुकेशन पोर्टल तथा मण्डल के मोबाइल एप के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समन्वयक संस्था तथा मण्डल के संभागीय कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी। जिले के भीतर परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं होंगे।

हायर सेकंडरी परीक्षा का संशोधित टाइम टेबल जारी, अब पहले दिन होगा केमिस्ट्री का पेपर

नसं, भोपाल । मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा बारहवीं की परीक्षा का संशोधित टाइम टेबल जारी किया है। मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षा 9 जून से होंगी, जो 16 जून तक चलेंगी। पहले यह एग्जाम 15 जून तक चलना थे। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार ये परीक्षा दो पालियो में होंगी। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। संशोधित टाइम टेबल के मुताबिक अब 9 जून को पहली पाली में पहला पेपर केमिस्ट्री का होगा। पहले वाले टाइम टेबल में पहला पेपर हायर मेथमेटिक्स का होना था। अब हायर मेथमेटिक्स का पेपर 15 जून को सुबह की पाली में होगा। इसके अलावा बोर्ड ने 10 जून के दोपहर की पाली वाले प्रश्नपत्र में भी संशोधन किया गया है। संशोधित टाइम टेबल के मुताबिक 10 जून को दोपहर की पाली मे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का पेपर होना था। अब यह प्रश्नपत्र 16 जून को दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा। पहले 15 जून को कैमिस्ट्री का पेपर होना था। अब 15 जून को विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास और वोकेशनल कोर्स का पेपर होगा। वहीं 11 जून को होने वाला अर्थशास्त्र का प्रश्नपत्र अब 16 जून को सुबह 9 से 12 बजे तक होगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले आना होगा। दरअसल परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर उन्हें पर्याप्त दूरी पर बैठाया जाएगा।

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी 28 मई से वेतन जनरेट करायें

रीवा। जिला कोषालय के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी आर.डी. चौधरी ने कहा है कि समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी माह मई 2020 की वेतन 28 मई तक अनिवार्य रूप से जनरेट करायें ताकि समस्त कर्मचारियों की वेतन एक जून को शत-प्रतिशत भुगतान कर जानकारी शासन को भेजी जा सके।

परीक्षा एवं परिणाम के लिए विश्वविद्यालय में हुई बैठक

कॉलेजों से छात्र संख्या एवं परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था का मांगा डाटा

स्टार समाचार | रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आगामी परीक्षा और पिछले परीक्षा के परिणाम को लेकर बैठक आयोजित हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पियूष रंजन अग्रवाल, कुलसचिव डॉ. बृजेश सिंह, प्रो. सुनील तिवारी और डिप्टी रजिस्ट्रार मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय ने सम्बद्धता रखने वाले कॉलेजों से फाइनल इयर स्नातक, स्नातकोत्तर में पढ़ने वाले छात्रों का डाटा मांगा है। साथ ही परीक्षा केन्द्रों में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए परीक्षा आयोजित कराई जाए, केन्द्रों में क्या व्यवस्थाएं हैं, आसपास के क्षेत्रों में और कितने केन्द्र बन सकते हैं इस पर योजना तैयार करने पर चर्चा हुई।

अटके हैं दो विषयों के परिणाम

विवि के अधिकारियों ने बताया कि लगभग सभी विषयों के रिजल्ट पहले ही जारी हो चुके हैं मगर बीएससी ऑनर्स केमेस्ट्री और एमए ऑनर एजुकेशन के रिजल्ट रुक गए हैं। दरअसल इन दोनों विषयों के परिणाम सेशनल और वाइवा के अंक जुड़ने के बाद जारी होते हैं मगर यह दोनों टेस्ट नहीं हो पाए। ऐसे में आधा अधूरा रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता और न ही इन विषम परिस्थितियों में सेशनल और वाइवा जैसे टेस्ट लेना उचित होगा। विश्वविद्यालय के अधिकारी इस समस्या का समाधान करने में जुटे हुए हैं। हालांकि ऐसी बात भी सामने आई है कि सेशनल और वाइवा ऑनलाइन आयोजित कराए जाएं। मगर ये ऑनलाइन कैसे सम्पन्न होंगे इसके लिए अभी योजना तैयार की जा रही है। विश्वविद्यालय इस प्रस्ताव को स्टैंडिंग काउंसिल के पास ले जाएगा, जिसके बाद ही इन दोनों विषयों के रिजल्ट के बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

29 जून के बाद होंगे एग्जाम

राजभवन से आए पत्र के अनुसार अगले महीने 29 तारीख के बाद पीजी और यूजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। जिसके बाद स्थितियां सामान्य होने के पश्चात अन्य कक्षाओं के एग्जाम होंगे। विश्वविद्यालय के लिए इस माहौल में परीक्षा आयोजित कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मगर शासन के निर्देश का पालन करते हुए अधिकारी बिना किसी चूक के परीक्षा आयोजित करने के प्रयास में जुट गए हैं। संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों से डाटा मांगा गया है। केन्द्रों की व्यवस्थाओं और छात्र संख्या का डाटा मिलने के बाद विश्वविद्यालय आगे की तैयारी करेगा।

लॉक डाउन के बाद 15 दिन तक लगेंगी स्पेशल कक्षाएं

ऐसा बताया गया है कि लॉक डाउन फेस-4 समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं से पहले 15 दिन तक स्पेशल कक्षाएं चलाई जाएंगी ताकि ऐसे पाठ्यक्रम जिनका सिलेबस अधूरा रह गया है वह पूरा हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग को मैंटेन करते हुए स्पेशल क्लासेस आयोजित की जाएंगी।

> विश्वविद्यालय ने सम्बद्धता रखते वाले कॉलेजों से परीक्षा केन्द्र एवं फाइनल इयर, स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का डाटा मांगा है। एग्जाम आयोजित करने के लिए यह एक प्राथमिक डाटा है। यह जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय आगे की रणनीति तैयार करेगा। सबसे पहले फाइनल इयर के यूजी और पीजी के छात्रों की परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाएंगी।
>
> - डॉ. बृजेश सिंह, कुलसचिव एपीएसयू

महिला अपराध शाखा कर रही जागरूक

एमपी में बच्चे को असहाय छोड़ना कानूनन अपराध

भोपाल। बच्चों को असहाय छोड़ देना, उनके साथ निर्दयी व्यवहार अर्थात शारीरिक दंड, मारपीट व गाली देना इत्यादि कृत्य कानूनन अपराध हैं। नाबालिग बच्चे की शादी करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। महिलाओं एवं बच्चों के कानूनी अधिकारों से संबंधित यह बातें पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा द्वारा चलाए जा रहे जन-जागरण कार्यक्रम के तहत आम जनमानस के ध्यान में लाईं जा रहीं हैं। जैविक माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को अनुशासित एवं नियंत्रण में रखने के लिए किए गए जायज उपाय अपवाद में आते हैं। पुलिस की महिला अपराध शाखा ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के साथ अमानवीय व निर्दयी व्यवहार करना जेजे एक्ट की विभिन्न धाराओं व नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। इसी तरह अवयस्क बच्चों से भीख मंगवाना भी गम्भीर संज्ञेय अपराध है। इस उद्देश्य के लिए बच्चे को शारीरिक क्षति पहुंचाना जेजे एक्ट की धारा 76 के तहत घृणित अपराध माना जाता है।

पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा ने बच्चों की जन्म तिथि से संबंधित सही दस्तावेज बनवाने की अपील भी की है। कानून में जन्म तिथि से सम्बंधित दस्तावेज बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे संबंधित दस्तावेजों मसलन जन्म प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी रिकार्ड, स्कूल में प्रवेश फार्म, दसवी की अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि में समान जन्म तिथि न होने पर बच्चे को परेशानी आ सकती है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु का पंजीयन भी कानूनी रूप से जरूरी है।

लेखन प्रतियोगिता में छात्र, शिक्षक के अलावा अभिभावक भी लेंगे हिस्सा

राज्य शिक्षा केंद्र ने अगले पांच सप्ताह तक आयोजन कराने की दी जानकारी

जागरण, रीवा। लॉकडाउन अवधि में सरकारी विद्यालयों के छात्रों हेतु लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में छात्र, शिक्षक के अलावा अभिभावक भी हिस्सा ले सकेंगे। इस बाबत राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी किए हैं। प्रतियोगिता में मुख्य रूप से प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। कुछ प्रतियोगिताओं में सभी वर्ग के छात्रों को भाग लेने की पात्रता रहेगी। बताया गया कि अगले पांच सप्ताह में पांच अलग-अलग विषयों में प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना है। यह प्रतियोगिता राज्य स्तर की होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधितों को विभाग के वाट्सअप नम्बर 9968556847 में सम्पर्क करना होगा। सभी वर्ग के लिए अलग-अलग विषय भी तय कर लिया गया है। उक्त निर्धारित विषय में ही लेखा आदि सामग्री प्रतियोगिओं को वाट्सअप नम्बर में भेजनी होगी। बता दें कि कोरोना वायरस से फैल रही महामारी को रोकने जिले में गत 21 मार्च से लॉकडाउन है। वहीं, सभी शिक्षण संस्थाएं गत 14 मार्च से ही बंद हैं। ऐसे में छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। हालाकि लोक शिक्षण संचालनालय व राज्य शिक्षा केंद्र निरंतर ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को विकसित कर संचालित करने में जोर दे रहा है। फिर भी कवायद पूरी होने में फोन नेटवर्क बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस लिहाज से ही राज्य शिक्षा केंद्र ने छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखने का यह तरीका निकाला है।

इस तरह चलेगा क्रम : बताया गया कि 17 से 23 मई तक कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले चुके हैं। इस अवधि में छात्र लॉकडाउन डायरी विषय में लेख विभाग के वाट्सअप नम्बर पर भेजे हैं। इसी तरह अब 24 से 30 मई तक होने वाली प्रतियोगिता में छात्रों के परिवार के बुजुर्ग सदस्य भागीदारी निभायेंगे, जो पीढ़ियों का ज्ञान विषय में लेख प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अलावा तीसरे सप्ताह 31 मई से 6 जून तक होगा, जिसमें छात्र के माता-पिता व अन्य अभिभावक परवरिश विषय में लेख लिखकर देंगे।

एक दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए बाध्यता नहीं

बाध्य किए जाने पर होगी कार्रवाई

जागरण, रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत आदेश जारी किये हैं कि जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं तथा स्कूल की यूनिफार्म विक्रेताओं को इस आशय की सूचना अपनी दुकान पर लगाना तथा उसका पालन करना अनिवार्य होगा की कोई भी व्यक्ति कितनी भी संख्या में पुस्तक या यूनिफार्म क्रय कर सकता है। उसे पुस्तकों का पूरा सेट खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। उन्होंने आदेश जारी किये कि प्रत्येक विद्यालय को अपने सूचना पटल पर उन दुकानों के नाम प्रदर्शित करना आवश्यक होगा जहां पर उस विद्यालय से संबंधित पुस्तकें तथा यूनिफार्म विक्रय हेतु उपलब्ध है साथ ही यह स्पष्ट करना होगा कि विद्यालय द्वारा किसी भी विशेष दुकान में क्रय करने की कोई बाध्यता नहीं है। प्रत्येक विद्यालय को अपने विद्यालय में चलन वाली पुस्तकों की सूची लेखक एवं प्रकाशक का नाम तथा मूल्य अपने विद्यालय के सूचना पटल पर एवं अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। यह जानकारी शाला के छात्रों एवं अभिभावकों के साथ ही कक्षा एक से 12वीं तक कक्षावार पुस्तकों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से संपूर्ण रीवा जिले में लागू होगा और उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में अनेक अशासकीय विद्यालय संचालकों द्वारा निजी प्रकाशनों की अनेक पुस्तकों का उपयोग विद्यालय के पाठ्यक्रम में किया जा रहा है। इसी प्रकार विद्यालयों में उनका अपना यूनिफार्म (ड्रेस कोड) आदि नियत है। यह पुस्तकें तथा यूनिफार्म आदि बाजार की किसी विशेष दुकान पर ही उपलब्ध है तथा पालकों को उक्त दुकान से ही क्रय करने का दबाव डाला जाता है। इसी प्रकार दुकानदार ग्राहकों को फुटकर पुस्तक न देकर पूरा सेट खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार की मोनोपाली कानूनी व नैतिक रूप से गलत है।

हर मामले में शिक्षक उपेक्षित

विभाग ने नहीं किया शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित

» अर्जित अवकाश से भी किया वंचित

» समग्र ने लिखा मुख्यमंत्री और अधिकारियों को पत्र

रायसेन। म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत प्रदेश के अनेक जिलों में शिक्षकों को कोरोना महामारी के विभिन्न आयामों में ड्यूटी पर लगाया गया हैं, लेकिन अन्य विभागों की भांति स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से इस बाबत निर्देश प्रसारित नहीं किया गए है, जिस कारण ड्यूटी के दौरान इस महामारी से प्रभावित होने पर मृत्यु की दशा में कोरोना योद्धा का शिक्षकों लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत सभी विभागों को निर्देश जारी किए थे, किंतु संगठन के बार-बार आग्रह के बावजूद दोनों विभागों की ओर से वर्तमान तक इस बाबत निर्देश प्रसारित नहीं किए हैं, जिससे शिक्षकों में भारी असंतोष है, शिक्षकों की इस समस्या की ओर समग्र शिक्षक संघ ने पत्र लिखकर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है, संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दुबे का कहना है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश है कि निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित एवं 55 वर्ष से अधिक आयु होने पर किसी कर्मचारी को कोरोना महामारी से जुड़ी किसी भी गतिविधि में सलग्न न किया जाए, इसके बावजूद कई जिलों में बीमार और 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को कोरोना महामारी से जुड़ी बचाव की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, समग्र जिला इकाई भोपाल के जिला अध्यक्ष महावीर शर्मा का कहना है कि यह प्रश्न शिक्षको के साथ उनके परिवारों की सुरक्षा से भी जुड़ा है, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए।

अर्जित अवकाश में भी भेदभाव

समग्र ग्वालियर जिला इकाई के जिला अध्यक्ष अमित उपमन्यु के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विश्राम अवकाश अवधि में कक्षा 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण/प्रशिक्षण में संलग्न किया गया है, किन्तु विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक/समग/2020/1747 भोपाल, दिनांक: 22 मई 2020 में केवल कक्षा 9 से 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षको को अर्जित अवकाश दिए जाने का उल्लेख किया है, संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दुबे के अनुसार इस संबंध में विभाग को पत्र लिखकर विश्राम अवकाश अवधि में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं में विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षण/प्रशिक्षण में शामिल प्रदेश के सभी शिक्षकों को समान रूप से अर्जित अवकाश की पात्रता घोषित करते हुए स्पष्ट निर्देश प्रसारित करने की मांग की गई है,वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि मुरारी लाल सोनी का कहना है कि मध्य प्रदेश के सभी विभागों ने अपने विभाग अंतर्गत कार्यरत लोक सेवकों को इस महामारी में लगाए जाने पर कोरोना योद्धा घोषित करने हेतु विभागीय स्तर से पत्र जारी किया है लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इस मुद्दे पर बार-बार आग्रह करने के बावजूद अमल नहीं किया गया है।

सामान एकत्रित कर सेवा भारती कार्यकर्ताओं को सौंपा

संक्रमण से पीड़ित मजदूरों के लिए शिक्षक समुदाय ने दिया राशन

स्टार समाचार | भिंड

शिक्षक समुदाय द्वारा सेवा भारती जिला भिंड को कोरोना संक्रमण में पीड़ित मजदूर गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए गत दिवस 12 क्विंटल आटा, एक क्विंटल चावल, 75 किलो तेल, 150 साबुन, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, नमक, के 75-75 पैकेट, 75 किलो अरहरकी दाल आदि सामग्री प्रदान की गई।

इस अवसर पर जिला सह संघ चालक सुनील अग्रवाल ने कहा कि शिक्षक समुदाय सदैव ही समाज के उत्थान के लिए तत्पर रहता है। भिण्ड का शिक्षक समुदाय 24 मार्च से लगातार कोरोना पीड़ितों, गरीब, मजदूर, विधवा, महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, निशक्त परिवारों को खाद्यान्नों की राहत सामग्री उपलब्ध करा रहा है। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए शीतल जल सेवा शहर के बस स्टेण्ड पर सतत रूप से संचालित की जा रही है। इसके लिए शिक्षक समुदाय भिंड के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। शिक्षक समुदाय की ओर से संदीप सिंह कुशवाह ने कहा कि शिक्षक समुदाय के सदस्य सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए सदैव एक सैनिक की तरह तैयार हैं एवं सामाजिक बुराइयों से निरंतर लड़ते हुए समाज को जागृत करने के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए अभी भी जन समुदाय में जन जागृति की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षक समुदाय मिलकर गांव-गांव में कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करता रहेगा। इस मौके पर नवल सिंह भदौरिया, संतोष गुप्ता, सुनील अग्रवाल, गजेन्द्र सिंह कुशवाह तथा शिक्षक समुदाय भिंड की ओर से राजू सिंह कुशवाह, संदीप सिंह कुशवाह, गगन शर्मा, परमाल सिंह कुशवाह, पंकज सोनी, वरुण सिंह भदौरिया, श्यामवीर सिंह भदौरिया, श्रीकांत सोनी, महेन्द्र सिंह भदौरिया, मनीष मिश्रा, गोविंद सिंह भदौरिया, राजेन्द्र लखेरे, दीपक राजावत, एनएसएस के छात्र एवं छात्राओं में लक्ष्मी भदौरिया, प्रिया तोमर, सोना ओझा, अंजली राजपूत, हरेन्द्र गौतम, हनु, शिवा गौतम, अनूप हरिऔध, हर्ष पंडित, शिवप्रताप राजावत आदि लोग मौजूद रहे।

लॉक डाउन के चलते मानदेय से वंचित रहे अंशकालिक शिक्षक

स्टार समाचार | रीवा

लॉक डाउन के चलते स्कूलों में पढ़ाने वाले अंशकालिक शिक्षकों को दो महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। दरअसल शिक्षकों के रिक्त पद में काम करने वाले अंशकालिक शिक्षकों को प्रति वर्ष 14 मार्च को कार्य से मुक्त कर दिया जाता है और कक्षाएं प्रारंभ होने के बाद फिर से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। मगर इस बार लॉक डाउन के चलते यह संभव नहीं हो पाया। गौरतलब है कि अंशकालिक शिक्षकों को काम के अनुसार भुगतान किया जाता है। इस बार अब तक स्कूलों की कक्षाएं ही नहीं शुरू हुईं और न ही अंशकालिक शिक्षकों को वेतन मिल सका। गौरतलब है कि लॉक डाउन फेस-3 से पहले तक सरकार ने किसी भी संस्था को कर्मचारियों की वेतन कटौती न करने के निर्देश दिए थे। मगर शासकीय स्कूल में ही काम कर रहे अस्थायी शिक्षकों के बारे में सरकार ने सोचा तक नहीं। अंशकालिक शिक्षकों का कहना है कि जिस तरह शासन व प्रशासन ने मार्च में 15 दिन और अप्रैल महीने का वेतन दूसरे स्कूलों के अंशकालिक शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों को दिया है उसी तरह शासकीय मॉडल हायर सेकेण्ड्री स्कूल के अंशकालिक शिक्षकों को भी दिया जाए। बताया गया है कि विद्यालय के 15 शिक्षकों को सन् 2019 में प्रत्येक वर्ष कक्षा शिक्षण एवं साक्षात्कार न कराए जाने की याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की थी।

डिजिटल शिक्षा के प्रति अभिभावकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत

भा.सं., रीवा| जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सुदामा प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि परिवर्तित परिदृश्य में डिजिटल शिक्षा सीखने का सशक्त माध्यम बन रहा है। परन्तु पहली बार डिजिलेप द्वारा प्रदाय की जा रही शिक्षा सामग्री का उपयोग कर रहे विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे सवालों और चुनौतियों का समाधान बच्चों से जीवंत संपर्क बनाए रखने से संभव है। डिजिलेप कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकों से नियमित संवाद करने के साथ कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों के पर्यवेक्षण हेतु संकुल समन्वयक, जन शिक्षा प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके तहत विद्यार्थियों को नियमित रूप से डिजिलेप संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार एवं अभिभावकों को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता लाना है। तथा यह सुनिश्चित करना है कि समूह में अभिभावकों को सही और समय से शिक्षण सामग्री भेजी जा रही है। स्वयं प्रतिदिन दो-तीन विद्यार्थी या अभिभावक तथा दो-तीन शिक्षकों के कार्यक्रम संबंधी फीडबैक लेना, शिक्षकों से प्रतिदिन चर्चा कर उन्हें टिप्पणियां तथा गृह कार्य शेयर करने और फोन, व्हाट्सएप के माध्यम से की गई समीक्षा की जानकारी संधारित करना, संकुल के समस्त शालाओं के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक के नियमित संवाद करना शामिल है। इसी प्रकार डिजिलेप, टीवी और रेडियो स्कूल कार्यक्रमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने वाले शिक्षकों को राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तर पर पुरस्कृत किए जाने संबंधी जानकारी तैयार करना है।

इग्नू| पन्द्रह जून तक जमा कर सकेंगे विद्यार्थी अपने असाइनमेंट

टर्म- एंड परीक्षाएं भी की गईं स्थगित

कार्यालय संवाददाता| रीवा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) ने जून 2019 के टर्म-एंड परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संचालित हो रहे इस पाठ्यक्रम के विभिन्न कोर्सेस के जरिए परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए यह एक बड़ी राहत की बात है। वह अब आगामी पन्द्रह जून तक ऑनलाइन असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पहले विद्यार्थियों को यह असाइनमेंट 31 मई 2020 तक जमा करने अनिवार्य किए गए थे। जानकारी रहे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) के जरिए प्रति वर्ष सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी अलग-अलग कोर्सेस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपने मनचाहे विषय से परीक्षाएं देते हैं।

लॉकडाउन के कारण बढ़ी तिथियां

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) ने परीक्षा कार्यक्रम में यह परिवर्तन कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण किया है। इस क्रम में असाइनमेंट की तिथि को भी आगे बढ़ा दिया गया है। इग्नू ने टर्म-एंड परीक्षाओं के लिए सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। उम्मीदवार ई-मेल के माध्यम से असाइनमेंट जमा कर सकते हैं।

लॉकडाउन खुलने के बाद अगला शेड्यूल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) ने इसके पहले जून 2020 की टर्म-एंड परीक्षा को भी स्थगित कर दिया था। जिसे वह पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 1 जून से आयोजित करने वाला था। कहा गया है कि अब कोरोना वायरस लॉकडाउन खुलने के बाद जल्द ही परीक्षा को नया शेड्यूल जारी किया जाएगा।

जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) ने आगामी जुलाई सत्र 2020 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। बताया गया है कि जो उम्मीदवार इग्नू के तहत दाखिला लेना चाहते हैं, वह अधिकृत वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) प्रबंधन ने 30 जून की अंतिम तारीख तय कर दी है। **इनके लिए लाभकारी**-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) के जरिए अपने पसंदीदा विषय पर डिग्री लेने की सुविधा होती है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से नियमित कोर्सेस के तहत अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। अपने किसी व्यवसाय आदि में व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए इग्नू अवसर उपलब्ध कराता है। यह एक ओपेन विश्वविद्यालय के रूप में विद्यार्थियों को मौका देता है। इसके जरिए कोई भी डिग्री कोर्सेस कर सकता है।

व्याख्याताओं को शीघ्र मिलेगा तृतीय समयमान वेतन

भास्कर न्यूज | सतना

स्कूल शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के तहत नियुक्त व्याख्याताओं को शीघ्र ही तृतीय समयमान वेतन का लाभ मिलेगा, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने संयुक्त संचालक रीवा के माध्यम से आवश्यक जानकारियां तलब की हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन सतना के अध्यक्ष श्रीश पांडेय के मुताबिक सीधी भर्ती वाले व्याख्याताओं को संकुल प्राचार्य के माध्यम से डीईओ ऑफिस में नियुक्ति आदेश के साथ-साथ प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति व पदोन्नति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करानी पड़ेगी, जिससे उक्त वेतनमान का लाभ समय रहते मिल सके।

सीबीएसई 12वीं परीक्षा • विषय विशेषज्ञों का कहना कि पूरी सावधानी के साथ होंगे पेपर, पहले चैक होगा स्टूडेंट्स का बॉडी टेम्प्रेचर

चेहरे पर मास्क... और एग्जाम हॉल में होगी एक मीटर की दूरी

एन्ट्री गेट- एंट्री गेट से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक से ज्यादा एंट्री गेट हो सकते हैं।

टेम्परेचर चैक- मास्क लगाकर पहुंचे छात्रों का बॉडी टेम्परेचर चैक होगा और हैंड सेनेटाइज किए जाएंगे, इसके बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में प्रवेश कर पाएंगे।

वॉटर-बॉटल- मौसम को देखते हुए यह संभावित है कि छात्रों को घर से ट्रांसपेरेंट वॉटर बॉटल लाने की अनुमति प्रदान की जाए।

मास्क- सेंटर में एंट्री से लेकर पूरी पेपर अवधि तक स्टूडेंट को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। क्लास में छात्रों की संख्या कम होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।

इन स्टेप्स को पार करना पड़ सकता है

सिटी रिपोर्टर, जबलपुर।

एग्जाम सेन्टर के बाहर सामाजिक दूरी के साथ स्टूडेंट्स की कतार होगी, चेहरे पर मास्क होगा और हाथों में वाटर बॉटल। अपने दोस्तों से वे बिना बात किए दूर से ही हाय हैलो करेंगे। गेट में ही बच्चों को सेनिटाइज कर उनका टेम्प्रेचर चैक किया जाएगा। क्लास रूमों में 1 मीटर का डिस्टेंस रखकर बैठना होगा। परीक्षा होने के बाद हाथों को सेनिटाइज करना होगा। इन सभी संभावित सावधानियों के साथ सीबीएसई कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरों में भी पेरेन्ट्स को एग्जाम के पहले बच्चों के स्वास्थ्य की प्रॉपर मॉनीटरिंग करनी होगी। तब कहीं जाकर कोरोना संक्रमण के समय बेहतर और सेफ तरीके से बच्चे एग्जाम देने में सफल होंगे। (आर-6)

फाइनल गाइडलाइन आनी है...

सीबीएसई को-ऑर्डिनेटर डॉ. राजेश कुमार चंदेल का कहना है कि एग्जाम कंडक्ट कराने की फाइनल गाइडलाइन सीबीएसई की ओर से अभी आनी बाकी है। हां कुछ जरूरी सावधानियों को सीबीएसई ने अपनाने को कहा है। जैसे कि सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एग्जाम करवाना। यह भी हो सकता है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए बच्चों को एग्जाम सेन्टर से दूर न किया जाए, इसके लिए उन्हें कुछ घरों से ट्रांसपेरेन्ट्स वाटर बॉटल लानी पड़े।

एग्जाम टाइम से पहले पहुँचना होगा

विषय विशेषज्ञा डॉ. अर्पणा चौबे बताती हैं कि एग्जाम के काफी समय पहले पेरेन्ट्स को बच्चों को लेकर एग्जाम सेंटर पहुँचा पड़ सकता है। क्योंकि वहाँ लंबी कतार होगी जिसमें बच्चों को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लाइन में लगकर अपना एडमिट कार्ड चैक कराना होगा और बोर्ड पर बिना हाथ लगाए, एक-एक कर अपने रोल नंबर के साथ उन्हें किस हॉल में बैठना है यह देखना होगा।

पेरेन्ट्स की निगरानी | प्रिपरेशन टाइम से लेकर पूरे एग्जाम तक पेरेन्ट्स को बच्चों की हेल्थ की मॉनीटरिंग करनी पड़ेगी। ताकि स्टूडेंट्स बेहतर स्वास्थ्य के साथ पेपर दे पाएं। अगर बच्चों में कोई लक्षण दिखाते हैं तो उनका चैकअप कराना जरूरी है। पे-2

टैड से खास केन रॉबिन्सन, ब्रिटिश लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर

क्या हमारे स्कूल बच्चों की रचनात्मकता खत्म कर रहे हैं?

टेड के मोस्ट पॉपुलर टॉक में शामिल केन रॉबिन्सन के इस वीडियो को 6 करोड़ 53 लाख से ज्यादा बार देखा गया है।

▮ सारे बच्चे जन्मजात क्रिएटिव होते हैं। चुनौती है कि वह उम्र बढ़ने के साथ भी क्रिएटिव बने रहें।'

- पिकासो

बच्चे क्रिएटिव होते हैं। लेकिन जब वही उम्र के पायदान चढ़ने लगते हैं, तो क्रिएटिविटी कम होती जाती है। आपने कभी गौर किया, क्यों? क्यों उम्र बढ़ने के साथ हमारी रचनात्मकता को जंग लग जाती है? इसका जवाब है कि पढ़-लिखकर हम अपनी रचनात्मकता खत्म कर लेते हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई के विषय लगभग एक से हैं। टॉप पर गणित और भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, उसके बाद ह्यूमेनिटीज और सबसे आखिर में आर्ट्स के स्टूडेंट्स का नंबर आता है। दुनिया में कहीं भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जहां हम बच्चों को रोज डांस उस तरह ही सिखाएं जैसे कि क्लास में मैथ्स सिखाते हैं। अगर गणित महत्वपूर्ण है, तो डांस भी जरूरी है। अगर बच्चों को डांस करने दिया जाए, तो क्या वह पूरे समय डांस नहीं करते रहेंगे।

हमारी शिक्षा प्रणाली अकादमिक योग्यता को ही सर्वेसर्वा मानती है, इसका एक कारण भी है। 19वीं शताब्दी के पहले दुनिया में पब्लिक एजुकेशन सिस्टम नहीं था। पढ़ाई का उद्देश्य उद्योगों की जरूरतों को पूरा करना था। धारणा रही कि उद्योगों में काम के लिए जरूरी विषय सबसे महत्वपूर्ण होंगे। सबका ध्यान अकादमिक योग्यता पर रहा। इस प्रक्रिया में हमारी असली इंटेलिजेंस कहीं खो सी गई। आप देखेंगे कि पूरा फोकस अब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एंट्रेस एग्जाम तक रह गया है। इस दौड़ में असल में प्रतिभावान, रचनात्मक और इंटेलिजेंट लोग पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी असली प्रतिभा की स्कूल में भी कद्र नहीं की जाती।

मैं अपनी किताब के लिए गिलेन लाइन नाम की महिला से मिला। गिलेन डांसर, कोरियाग्राफर होने के कारण टीवी और फिल्म जगत का जाना-पहचाना नाम है। गिलेन को बचपन में लिखने-पढ़ने में तकलीफ थी, उसके पैरेंट्स एक स्पेशलिस्ट के पास ले गए। मां-बाप को गिलेन से ढेरों शिकायतें थीं। स्पेशलिस्ट ने सबकी बात सुनकर आठ साल की गिलेन को कमर में अकेला छोड़ दिया और रेडियो चालू कर दिया। थोड़ी देर में गिलेन ने डांस करना चालू कर दिया। बाद में गिलेन ने रॉयल बैले स्कूल से पढ़ाई भी की और आज वह अरबपति और सफल महिला हैं।

लब्बोलुबाब है कि बच्चों को क्रिएटिव बने रहने दीजिए...तभी वह सही मायनों में सफल हो पाएंगे।

संभावना

ऑनलाइन स्टडी दायरा बढ़ाएगी, लेकिन क्लास रूम का अपना महत्व

भविष्य में बहुत से संस्थान स्टडी मटेरियल के डिजिटाइजेशन पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

सिद्धार्थ चतुर्वेदी
निदेशक, आईसेक्ट समूह

वर्तमान समय में बैठ यदि हम भविष्य में झांके तो मुझे ऑनलाइन स्टडी अपना स्पेस बढ़ाते हुए दिख रही है। ये सशक्त रूप में उभर रही है। लेकिन इसके मायने ये नहीं कि क्लास रूम का महत्व कम हो जाएगा। इस समय डिजीटल और क्लास रूम स्टडी के बीच के अनुपात को 20 : 80 मान लें तो आने वाले समय में ये 50: 50 हो सकता है।

कोविड-19 से स्कूली बच्चों के अभिभावक चिंता में हैं। जो कि जायज भी है। उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति अलग है। यहां युवा समझदार और जिम्मेदार होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कक्षाएं चल सकती हैं। कोरोना वायरस ने सभी देशों को कई सीख दी हैं। इस महामारी ने बताया कि अब लगभग हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन अपनाते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा। शिक्षा भी उन क्षेत्रों में से एक है। लॉकडाउन के बीच कई जगह इसकी शुरुआत हो चुकी है। कई शिक्षक और छात्र डिजिटल लर्निंग से काफी हद तक वाकिफ भी हो चुके हैं। इसे देखकर भविष्य में बहुत से संस्थान स्टडी मटेरियल के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। हालांकि क्लासरूम आधारित शिक्षा को नहीं हटाया जा सकता।

ग्रामीण युवाओं का घटेगा खर्च

इसका बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा जो कई बार शहर के भारी भरकम खर्च का भार वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे में वे अपने घर में रहते हुए भी शिक्षा को पूरा कर सकेंगे।

डिजिटल वर्ल्ड में अब नए विषय

टेक्नोलॉजी की ताकत से कोरोनावायरस से हुए नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सका। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है। तकनीक के इस प्रभाव से नए कोर्सेज जैसे डाटा साइंस, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ रोबोटिक्स, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, आदि कोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी। जॉब्स रीक्रियेट हो रही हैं परन्तु स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी समस्या है।

डीएवीवी : परीक्षाओं को लेकर सांसद लालवानी ने बुलाई बैठक

प्राचार्य और छात्रों की राय से होंगी परीक्षाएं

पत्रिका

इंडेप्थ स्टोरी

इंदौर @ पत्रिका. कोरोना संक्रमण के कारण यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित करना पड़ी है। यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा पहले कराना चुनौती है। इनके साथ बाकी परीक्षाएं कब और कैसे होंगी इन सवालों के जवाब के लिए मंगलवार को सांसद शंकर लालवानी ने कुलपति व अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें सहमति बनी कि जल्द ही नेहरू स्टेडियम में बैठक रखी जाएगी, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, प्रोफेसर, शिक्षाविद् और हर कॉलेज से 5 छात्र शामिल होंगे और अपनी राय देंगे।

बैठक में कुलपति प्रो. रेणु जैन, कोरोना से लड़ाई में राज्य सरकार के सलाहकार डॉ. निशांत खरे, कलेक्टर मनीष सिंह और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार अनिल शर्मा शामिल थे। लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई है और शैक्षणिक गतिविधियां ठप है। सांसद लालवानी ने कहा, छात्रों का स्वास्थ्य प्राथमिकता है। आपदा के इस कठिन समय में चीजें प्रभावित होंगी, लेकिन कोरोना से बचाव की सावधानियां रखते हुए परीक्षाओं का आयोजन कैसे हो इस पर विचार किया गया है। डॉ. खरे ने कहा, सबसे पहले फाइनल ईयर की परीक्षाएं हों, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य के फैसले लेने में देरी न हो। यूनिवर्सिटी के विभागों में सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर जानकारी दी गई कि अभी आधे से कम कर्मचारी ही बुलाए जा रहे हैं।

कोविड-19 के बढ़ते दायरे को देख लिया फैसला

दीक्षांत, वार्षिकोत्सव तो दूर वर्कशॉप और सेमिनार भी नहीं कराएगी यूनिवर्सिटी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं पर जारी मंथन के बीच अगले सत्र में सुरक्षा के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसके तहत सत्र 2020-21 में किसी भी बड़े आयोजन को नहीं कराने पर विचार हो रहा है। किसी भी स्थिति में भीड़ जुटने से रोकी जाए, इसलिए यूनिवर्सिटी की बैठकें भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से होंगी।

कोविड-19 के कारण लॉकडाउन से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की भी छुट्टियां चल रही थीं। मंगलवार से कुछ विभागों के ताले खुले और फैकल्टी व अन्य स्टाफ पहुंचा। विभागाध्यक्षों ने कक्षाओं, स्टाफ रूम, ऑडिटोरियम आदि का निरीक्षण कर हर जगह सेनिटाइज कराने की बात कही। इस बीच यह सवाल उठा कि विभागों में तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी लेकिन बड़े सेमिनार, वर्कशॉप, वार्षिकोत्सव और दीक्षांत समारोह जैसे आयोजनों में क्या इंतजाम होंगे। ज्यादातर विभागाध्यक्ष ऐसे सभी समारोह एक सत्र के लिए निरस्त करने के पक्ष में नजर आए। उनका कहना था कि ऐसे दौर में कक्षाएं लगाना ही चुनौतिपूर्ण है, वर्कशॉप और सेमिनार में बाहर से भी एक्सपर्ट्स को बुलाना होता है। स्थिति सामान्य होने के बाद भी हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। मालूम हो, 2017-18 और 2018-19 सत्र का दीक्षांत समारोह 23 मार्च को प्रस्तावित था, जिसे कोरोना के कारण स्थगित करना पड़ा है।

यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी डॉ. चंदन गुप्ता कहना है कि मंगलवार से विभाग खोले गए हैं। अभी किसी भी विभाग में कक्षाएं नहीं लग रही हैं। सेनिटाइज करने के बाद ही छात्रों को बुलाया जाएगा।

आरजीपीवी : सरकार ने नोटिस देकर पूछा

तकनीकी अतिथि विद्वानों का वेतन क्यों रोका गया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. आरजीपीवी से निकाले गए 100 से ज्यादा तकनीकी अतिथि विद्वानों को वेतन न देने के मामले में डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन प्रो. वीरेंद्र कुमार फिर सरकार के निशाने पर हैं।

प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा कार्यालय ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि जब सामान्य प्रशासन विभाग ने पूरे प्रदेश में यह आदेश जारी कर रखा है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जाएगा तो किस आधार पर वेतन रोकने की कार्रवाई की गई। वीरेंद्र कुमार को 15 मई को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल जवाब मांगा गया था। 26 मई को दूसरा नोटिस जारी होने के बाद डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन ने आनन-फानन में प्रदेश के सभी तकनीकी कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन को पत्र लिखकर जानकारी 1 घंटे के अंदर भेजने कहा लेकिन शाम तक किसी भी कॉलेज ने इस प्रकार की जानकारी नहीं भेजी।

आरजीपीवी कुलपति सुनील कुमार गुप्ता पर तकनीकी अतिथि विद्वानों ने आरोप लगाया है कि डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन प्रो. वीरेंद्र कुमार के साथ मिलकर 2 महीने तक बगैर वेतन काम कराने के बाद उन्हें पिछली तारीखों में नोटिस जारी कर नौकरी से निकाल दिया गया है। इस मामले की शिकायत प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन तक हुई है।

डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन एवं आरजीपीवी के कुलपति पहले तकनीकी कॉलेजों में संचालित किए जाने वाले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की खरीदी को लेकर भी जांच के घेरे में आ चुके हैं।

जिज्ञासा का समाधान

ग्रामोदय विवि में छात्रों को मिला ऑनलाइन परामर्श

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

चित्रकूट. कोरोना आपदा के कारण विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान और उनमें आत्मबल के विकास के लिए कुलपति नरेश चंद्र गौतम की प्रेरणा से मंगलवार को ग्रामोदय विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से सीधा संवाद ऑनलाइन के जरिए किया। छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए यह आयोजन छात्र कल्याण अधिष्ठान की ओर से संपन्न हुआ। जिसका संयोजन अधिष्ठाता प्रो. शशिकांत त्रिपाठी ने किया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुलसचिव डॉ. अजय कुमार, कला संकाय के अधिष्ठाता प्रो. वाईके सिंह, विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय के अधिष्ठाता प्रो. आईपी त्रिपाठी, प्रबंधन संकाय के अधिष्ठाता प्रो. अमरजीत सिंह, कृषि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. डीपी राय, अभियांत्रिकी संकाय के अधिष्ठाता डॉ. एके पांडे, दूरवर्ती कार्यक्रम के निदेशक प्रो. वीरेंद्र कुमार व्यास, शोध निदेशालय के निदेशक प्रो. आरसी त्रिपाठी, महाविद्यालय योजना के निदेशक प्रो. भरत मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक डॉ. नीलम चौरे, उपकुलसचिव डॉ. जितेंद्र कुमार शर्मा और डॉ. कमलेश कुमार थापक, उपकुलसचिव अकादमी डॉ. कुसुम सिंह, केंद्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष प्रो. रघुवंश प्रसाद बाजपेयी और मनोवैज्ञानिक प्रो. नंद लाल मिश्रा आदि शैक्षणिक व प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे।

सीबीएसई ने स्वास्थ्य-डिजिटल लॉ जैसे विषय किए शामिल

9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

भोपाल ◆ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन सुरक्षा, उनके डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं के मद्देनजर साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है।

इसका मकसद बच्चों के अंदर सेफ और हेल्थी आदतों को विकसित करना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों की डिजिटल दुनिया में पहुंच काफी बढ़ गई है और लॉकडाउन में ऑनलाइन कक्षाएं और स्टडी एक्टिविटी कराई जा रही है। ऐसे समय में सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया यह साइबर सेफ्टी मैनुअल स्टूडेंट्स के लिए काफी मददगार साबित होगा।

सुरक्षा संबंधी कई विषय शामिल

बोर्ड ने इस मैनुअल में ऑनलाइन धमकी, इमोशनल टॉर्चर, सामाजिक बहिष्कार, धमकाना, ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, साइबर कट्टरपंथ, धोखाधड़ी जैसे मामलों से सुरक्षा संबंधी विषय शामिल किए हैं। इसमें डिजिटल नागरिकता के आयामों का जिक्र किया गया है। जिसमें डिजिटल एक्सेस, साक्षरता, संवाद, आचार, स्वास्थ्य, अधिकार, स्वतंत्रता, डिजिटल लॉ आदि शामिल हैं।

अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन ने डे केयर और प्रि स्कूल के लिए जारी किए ऑफ्टर कोविड-19 सजेशन

टीचर्स और स्टाफ को दें हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंस की ट्रेनिंग, बड़े बच्चों के साथ शुरू करें स्कूल

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

इंदौर ◆ अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन ने प्रि स्कूल और डे केयर के लिए एक कैरिकुलम तैयार किया है। इस कैरिकुलम में एसोसिएशन ने स्कूलों और डे केयर को स्कूल शुरू होने पर रखी जाने वाली सावधानियां बताई हैं, ताकि बच्चों को कोविड19 के संक्रमण से बचाया जा सके। कैरिकुलम को तीन कैटेगिरी में बांटा है। इनमें स्कूलों

और डे केयर में बरती जाने वाली सावधानियां जैसे टीचर्स और स्टाफ ट्रेनिंग व इसके साथ पैरेंट्स व बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शामिल हैं।

कोविड-19 के बाद जब स्कूल शुरू हों, स्कूलों और डे केयर को केवल बड़े बच्चों को बुलाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को अल्टरनेट डे पर बुलाना चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। एसोसिएशन ने कहा कि स्कूल शुरुआत में ब्लेंडेड एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दें। इसके साथ ही स्कूलों में सेनेटाइजेशन की व्यवस्था पूरी हो और स्कूल बसों को भी प्रॉपर सेनेटाइज किया जाए।

स्कूल और डे केयर को बच्चों का मेडिकल रिकॉर्ड भी लेना चाहिए। एसोसिएशन ने सुझाव में कहा कि कोविड-19 के बाद वे संक्रमण के दौरान बच्चों और उनके परिवार की ट्रेवल हिस्ट्री जानें, जिससे अन्य बच्चे संक्रमण से बच सकें।

इसके साथ ही टीचर्स और स्टाफ के लिए हाइजीन मेंटेन रखने और बच्चों की केयर करने के लिए स्कूल ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित करें।

एसोसिएशन ने देश भर में मौजूद अपने सभी चैप्टर्स में यह कैरिकुलम भेजा है। हमारा उद्देश्य बच्चों को संक्रमण से बचाना है और इसके लिए वैरिकुलम के सुझावों को हम विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि स्कूल और डे केयर इन सुझावों का पालन कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

परवनी डावर, प्रमुख अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन, इंदौर

फीस के मुद्दे पर नहीं मिली राहत

पालक महासंघ नाराज, लॉकडाउन के बाद आंदोलन की तैयारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फीस समायोजित करने के आदेश जारी होने के बाद भी कई निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। पालक महासंघ सहित बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दखल के बाद भी विभागीय अधिकारी निजी स्कूलों की शिकायतों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कारवाई न होने से नाराज मप्र पालक महासंघ आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है। लॉकडाउन के बाद महासंघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में जिला स्तर पर आदोंलन करने के मूड में हैं। स्कूल शिक्षा विभाग सहित बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष कई बार फीस का मुद्दा उठाया है।

अधिकारी नहीं दिखा रहे रुचि

आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कारवाई को लेकर विभागीय अधिकारियों की कोई रुचि नजर नहीं आ रही है। नतीजन कई निजी स्कूल फीस को लेकर मनमानी कर रहे हैं और अभिभावक परेशान हो रहे हैं। अब पदाधिकारियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा।

जिले के माध्यमिक शिक्षकों को शीघ्र मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ

संभागीय उपायुक्त ने दिए कमेटी बनाने के निर्देश

मण्डला, (आरएनएन)। अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षण संवर्ग में संविलियन के बाद से ही काफी दिनों से माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति का मामला लटका पड़ा था। ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के काफी जद्दोजेहद के बाद मंडला जिले में 12 वर्ष पूर्ण कर चुके माध्यमिक शिक्षकों की सूची संभागीय उपायुक्त कार्यालय जबलपुर पहुंचाई गई, लेकिन महीनों तक वहां भी इस पर आगे की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। शुक्रवार को ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष डीके सिंगौर ने संभागीय उपायुक्त भारतीया साहब से मिलकर 12 वर्ष पूर्ण कर चुके माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति सूची को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

संभागीय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सिर्फ मंडला जिले से ही माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति संबंधी फाइल संभागीय कार्यालय पहुंची है। इस पर प्रांत अध्यक्ष डीके सिंगौर द्वारा शिक्षकों को हो रही मानसिक एवं आर्थिक क्षति का हवाला देकर जमा फाइलों के अनुसार ही क्रमोन्नति आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया, जिस पर संभागीय उपायुक्त ने तत्काल कार्यवाही करते हुए कमेटी गठन करने और फाइलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रांत अध्यक्ष से कहा कि कार्रवाई पूर्ण होने के बाद, आदेश जारी होने के पूर्व एक बार सूची का अवलोकन कर लें ताकि किसी का नाम छूट ना जाए। इसके बाद जिले के माध्यमिक शिक्षकों की बहु प्रतीक्षित क्रमोन्नति की मांग शीघ्र पूर्ण होने की संभावना बढ़ गई है।

जिले के माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ देने में देरी

टीचर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन

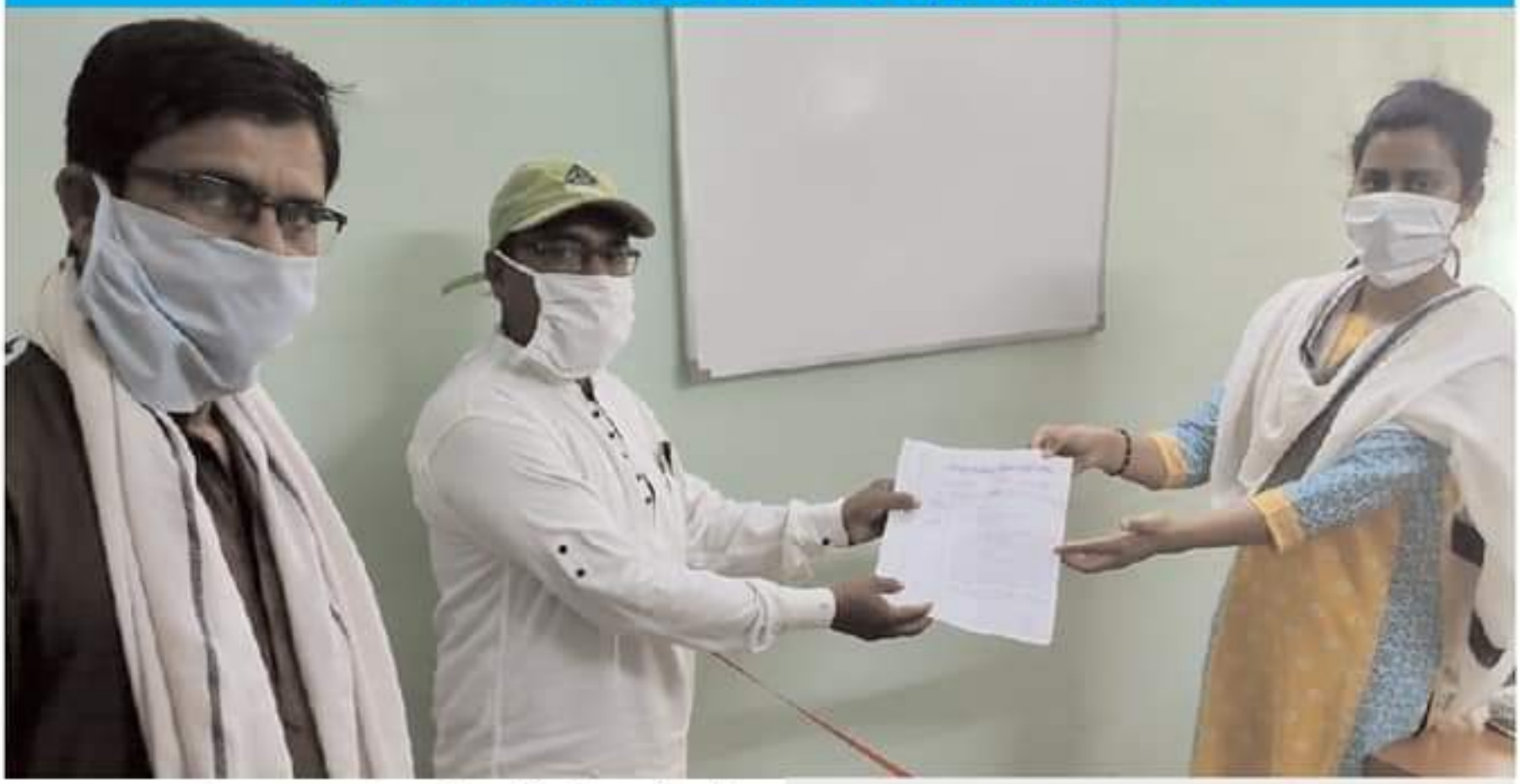

मण्डला, (आरएनएन)। ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने प्राथमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति को लेकर प्रांत अध्यक्ष डीके सिंगौर के मार्गदर्शन में ब्लॉक स्तर पर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक शाखा नैनपुर में अध्यक्ष अमर सिंह चंदेला प्रांतीय प्रवक्ता संजीव सोनी, नफीस खान, मनीष कटकवार द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी शिवानी सिंह तथा बिछिया में ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार बघेल, असित लोध, चंद्रशेखर तिवारी, सुरजीत पटेल, गोपाल राजपूत, मंसाराम झारिया ने तहसीलदार कमलचंद सिंगसौर को ज्ञापन सौंपा।

एसोसिएशन ने ज्ञापन में लिखा कि 2018-19 में 12 वर्ष पूर्ण कर चुके शेष प्राथमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति में अनावश्यक देरी की जा रही है। जिससे उनका सातवें वेतनमान का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। जबकि उनके साथ के शिक्षकों को दो महीने पूर्व क्रमोन्नति दे दी गई, किन्तु शेष शिक्षकों को क्रमोन्नति नहीं देने का अब तक सही कारण नहीं बताया जा रहा है, ना ही इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है।

प्रोफाइल पंजीयन के संबंध में बीईओ से चर्चा

एसोसिएशन के ब्लॉक शाखा नैनपुर के पदाधिकारियों ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी नैनपुर से मिलकर सातवें वेतनमान एवं ग्रीन कार्ड के लाभ से वंचित नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों का इस माह सही निर्धारण के साथ वेतन बनाने का अनुरोध किया। जिस पर बीईओ ने तत्वरित कार्यवाही करते हुए संकुल केंद्र सालीवाड़ा, पाठासिहोरा, नवीन हाई स्कूल नैनपुर एवं जामगांव के प्राचार्य को फोन पर 2 दिन में इस लाभ से वंचित शिक्षकों की जानकारी जमा कराने के निर्देश दिए। इसी तरह एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एम्पलाई कोड से वंचित ब्लॉक के सभी शिक्षकों के जिला स्तर से एमप्लाई कोड जारी कराने एवं प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों की प्रोफाइल पंजीयन के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की। जिस पर अधिकारी ने शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराने का आश्वासन दिया।

कंटेनमेंट एरिया में रहती हैं बीईओ, बाहर निकलने पर है प्रतिबंध, बैरियर पर फाइलें बुलाकर कर रहीं हस्ताक्षर

उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य भी हैं आयशा कुरैशी, 12 दिन से एरिया सील है, बाहर जाने की नहीं है अनुमति

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

मारुति नगर में कोरोना के 5 और मौलाना आजाद मार्ग में 3 पॉजिटिव केस निकलने के बाद हुड़ा क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया और पानी की टंकी के पास की चौकी पर बैरिकेड्स लगाकर एरिया सील कर दिया गया। तब से यहां के लोगों का बाहर जाना और बाहर के लोगों का अंदर आना मना है।

इसी क्षेत्र में झाबुआ की खंड शिक्षा अधिकारी और उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य आयशा सैयद कुरैशी का भी घर हैं। उन्हें भी बाहर जाने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में वो अपना सरकारी काम पुलिस बैरियर के पास लगी टेबल पर निपटा रही हैं।

कुरैशी ने बताया, जो काम घर से हो सकता है, वो घर से कर रही हूं। दिनभर में दर्जनों फाइलें निपटाना पड़ती है। सैकड़ों कागज पर साइन लगते हैं। नोटशीट चलाना पड़ती है। ऐसे में स्टाफ वालों से फोन पर बात कर दस्तावेज तैयार कर बैरिकेड के पास बुला लेती हूं। यहीं पुलिस की एक टेबल-कुर्सी रखी है। यहां फाइलें देखकर साइन कर देती हूं। कुल मिलाकर सारा काम घर और इस टेबल से चल रहा है। उम्मीद है एक-दो दिन में कंटेनमेंट एरिया खत्म हो जाएगा और ऑफिस जाकर काम कर सकूंगी।

बीईओ कुरैशी बैरिकेड के पास फाइलें बुलवाकर कर रहीं ऑफिस का काम।

यहां के 5 मरीज ठीक हो चुके : मारुति नगर के पहले मरीज हुसैन अली की 18 मई को मौत हो चुकी है। उनके बाद पॉजिटिव आए 5 मरीजों को ठीक होने के बाद सोमवार को छुट्टी दे दी गई। मारुति नगर में अब कोई केस नहीं है। मौलाना आजाद मार्ग में एक महिला जो अब ठीक हो चुकी है, उसकी एक भतीजी और एक भांजी की रिपोर्ट 15 मई को पॉजिटिव आई थी। वो अभी कोविड केयर सेंटर में हैं। मंगलवार को उन दोनों सहित 108 एंबुलेंस के दो इएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) के सैंपल भेजे गए। निगेटिव आने पर उन्हें भी छुट्टी दे दी जाएगी।

आदेश • परीक्षा देने वाले हर विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, प्रवेश पत्र को ही 'पास' माना जाएगा

होम क्वारेंटाइन छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे

ऐसे विद्यार्थियों को पूरक की देना होगी परीक्षा

भास्कर संवाददाता | खंडवा

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हायर सेकंडरी के बचे विषयों की परीक्षा 9 जून से 15 जून तक ली जाएगी। परीक्षा से पहले पूरे केंद्र, कक्षों के साथ परीक्षार्थियों को सैनिटाइज किया जाएगा। एक-एक परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जो परीक्षार्थी होम क्वारेंटाइन रहेंगे, वे मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन्हें पूरक परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

परीक्षा का समय सुबह 9 से 12 व दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण व लॉकडाउन के चलते परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला शिक्षाधिकारियों को नए दिशा-निर्देश दिए गए और उनका पालन कराने को कहा गया। कितने बच्चे कंटेनमेंट क्षेत्रों में हैं, कितने केंद्र रहेंगे, कितने बढ़ाए जाएंगे, इन सभी बिंदुओं पर तैयारियों के बाद फाइल कलेक्टर के पास जाएगी।

परीक्षार्थियों को घर से ही लाना होगा पीने का पानी

परीक्षार्थियों को जो प्रवेश पत्र दिए जाएंगे वे परीक्षा के दौरान पास का भी काम करेंगे। विद्यार्थी के साथ एक व्यक्ति मान्य रहेगा। रास्ते में पुलिस के रोकने पर विद्यार्थी को प्रवेश पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा थर्मल स्केनर स्कूल प्रबंधन को ही खरीदना होगा। परीक्षार्थी पीने का पानी घर से ही लेकर आएंगे। अगर परीक्षा केंद्र पानी पिलाएगा तो वह परीक्षार्थियों को गर्म करके देगा। होम क्वारेंटाइन परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा में बैठाया जाएगा। छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले परीक्षार्थी वापस छात्रावास में आकर पढ़ाई कर परीक्षा दे सकेंगे।

जो क्वारेंटाइन हैं वे पूरक देंगे

पुराने प्रवेश पत्र ही परीक्षा के लिए मान्य होंगे। इन्हें पास भी माना जाएगा। जो परीक्षार्थी कंटेनमेंट क्षेत्रों से होंगे वे परीक्षा दे सकेंगे जबकि क्वारेंटाइन किए गए परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

-जेएल रघुवंशी, जिला शिक्षाधिकारी

12,500 विद्यार्थी देंगे परीक्षा

जिले में 12 हजार 500 विद्यार्थी 78 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर हमने तैयारी शुरू कर दी है। जो विद्यार्थी बाहर से परीक्षा देना चाहते हैं उनके ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू हो गए हैं। ऐसा केंद्र जो कंटेनमेंट एरिया में है, उसे बदला जा सकता है।

-आरके सेन, बोर्ड परीक्षा प्रभारी व प्राचार्य

गाइडलाइन • मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूलों को निर्देश, एक साल तक रहेंगे लागू

सर्दी-जुकाम हुई तो 15 दिन स्कूल नहीं आ सकेंगे शिक्षक-विद्यार्थी

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू होने वाले स्कूलों में अगले एक साल तक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सख्ती रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सर्दी-जुकाम होने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी और शिक्षक के स्कूल आने पर 15 दिन के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। इस दौरान पढ़ाई ऑनलाइन होगी।

यह निर्देश स्कूल खुलने के बाद अगले 1 साल तक लागू रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल में कक्षाएं शुरू होने के बाद जिन शिक्षक या विद्यार्थी को सर्दी-जुकाम आदि की दिक्कत होगी। उन्हें अगले 15-20 दिन स्कूल आने से रोका जाए। ऐसे शिक्षक घर से ही ऑनलाइन क्लास लेंगे। वहीं ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षक स्कूल में पढ़ाए गए चैप्टर को ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई छूटे नहीं।

कोरोना पॉजिटिव हो तो खुद स्कूल आना करेंगे बंद

एचआरडी ने स्कूल के शिक्षकों के लिए भी गाइडलाइन बनाई है। इसमें कहा गया है कि गले, मुंह, नाक आदि में इंफेक्शन की शिकायत होने पर शिक्षक खुद ही घर से पढ़ाई कराना शुरू करेंगे। अगर किसी शिक्षक को खुद में कोरोना के लक्षण लगें तो वे तुरंत प्राचार्य से संपर्क कर स्कूल आना बंद करेंगे। इसके अलावा इलाज के साथ ही खुद को आइसोलेट करेंगे। ऐसे शिक्षक किसी भी विद्यार्थी के सीधे संपर्क में नहीं आएंगे। इन्हें नोटबुक की जांच के साथ-साथ स्कूल के अन्य शैक्षणिक कामों से भी दूर रखा जाएगा। यदि शिक्षक खुद ऐसी पहल करते हैं तो ऐसे शिक्षकों को कोरोना योद्धा के तौर पर स्कूल सम्मानित करेगा। स्कूलों के रूटीन को लेकर भी एचआरडी ने सीबीएसई को गाइडलाइन भेजी है।

नोटबुक जांचने से पहले करना है सैनिटाइज

अभी तक शिक्षक पढ़ाते थे और बच्चों की नोटबुक चैक करते थे, लेकिन अब यह कुछ घंटों के बाद होगा। विद्यार्थी द्वारा नोटबुक जमा की जाएगी। इसके कुछ घंटों बाद ही शिक्षक उसे छूएंगे। छूने से पहले सभी नोटबुक को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद ही शिक्षक नोटबुक में सुधार करेंगे।

जून में शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया

: केंद्रीय विद्यालय गेल में इन दिनों समर वैकेशन चल रहे हैं। लॉकडाउन के चलते इस बार यहां अप्रैल नहीं लगी। हर साल अप्रैल से मई तक केंद्रीय विद्यालय में कक्षाएं संचालित होती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार ऐसा नहीं हुआ। उधर, जल्द ही यहां के लिए नए एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। स्कूल प्रबंधन के पास अब तक इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जानकारी के अनुसार नए एडमिशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया जून में शुरू हो सकती है।

स्कूल व कॉलेज की बची परीक्षाओं पर विद्यार्थी और परिजन के सवालों से जुड़ी दो खबरें

कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं होगी 12वीं की परीक्षा, कॉलेजों को बना सकते केंद्र

9 जून से सीबीएसई की परीक्षा को लेकर अफसरों ने दिए निर्देश, 136 केंद्रों में 50 संवेदनशील क्षेत्र में हैं

भास्कर संवाददाता | इंदौर

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा 9 जून से होना है। इसके लिए बनाए गए कुल 136 में से शहर के 50 से ज्यादा परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट एरिया में हैं। इसे देखते हुए भोपाल के शिक्षा विभाग के अफसरों ने राय दी है कि सीबीएसई स्कूल के अलावा कॉलेजों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। इसकी सूची जल्दी ही तैयार कर कलेक्टर को सौंपी जाए।

मप्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव अनिल सुचारी ने मंगलवार दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीईओ, जेडी, जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि नए सेंटरों को बनाए जाने को लेकर कार्रवाई कर उसकी लिस्ट संबंधित कलेक्टर को सौंपें, ताकि वे उसके मुताबिक व्यवस्थाएं कराएं।

रोल नंबर को ही पास के रूप में अनुमति देने पर चल रहा विचार

लॉकडाउन में सिर्फ पासधारी ही बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में छात्रों के लिए उनके रोल नंबर को ही पास के रूप में मान्यता देने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा छात्रों के साथ एक पालक को भी जाने की अनुमति दी जा सकती है।

थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जाएगा ख्याल

परीक्षा केंद्रों में पहुंचने वाले छात्रों के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी रहेगी। परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके, इसके लिए एक ही दिन में हो रहे दो पेपरों को आगे बढ़ाया गया है। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 9 जून से 15 जून तक चलना थी, लेकिन अब एक दिन और बढ़ जाएगी। ऐसे में परीक्षा 16 जून को होगी। इस बारे में संशोधित टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जाएगा।

बाहरी छात्रों को कहां ठहराओगे व खाना-पीना कहां होगा: अभिभावक

कॉलेजों की परीक्षाओं के लिए व्यवस्था को लेकर सांसद, कलेक्टर और कुलपति में हुई चर्चा

भास्कर संवाददाता | इंदौर

कोरोना संकट के बीच 29 जून से 31 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाओं को लेकर मंगलवार को सांसद शंकर लालवानी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और कलेक्टर के साथ बैठक की। इसमें तय किया गया कि परीक्षा पर योजना बनाने के लिए नेहरू स्टेडियम में एक बड़ी बैठक होगी। इसमें कॉलेज प्राचार्य, प्रोफेसर और हर कॉलेज से 5 छात्र शामिल होंगे। इस बीच अभिभावकों और छात्रों के कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब भी मिलना बाकी है।

- यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में 35 फ़ीसदी से ज्यादा छात्र बाहर हैं। वे ऐसे हालात में अन्य शहरों से कैसे आएंगे।
- बाहर के राज्यों से आने वाले हजारों छात्रों को 14 दिन का क्वारेंटाइन जरूरी होगा। इनकी व्यवस्था कैसे होगी।
- अगर परीक्षा के दौरान या इंदौर आते समय कोई कोरोना का शिकार हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
- सारे होस्टल बंद हैं। ऐसे में प्रदेश के अन्य शहरों से आने वाले हजारों छात्रों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था कौन करेगा?
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सीमित संसाधनों में परीक्षा केंद्र कैसे कर पाएंगे ?
- जून-जुलाई में भारी बारिश होती है। ऑटो, बसें, टैक्सी बंद हैं। ऐसे में छात्र परीक्षा केंद्र तक कैसे पंहुचेंगे?

फिलहाल 30 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे यूनिवर्सिटी

बैठक में फिलहाल यूनिवर्सिटी के 30 फीसदी कर्मचारियों को आने के लिए कहा जाएगा। ताकि काम शुरू किया जा सके। बाद में धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जाएगा। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. रेणु जैन, रजिस्ट्रार अनिल शर्मा, सरकार के सलाहकार डॉ. निशांत खरे और यूनिवर्सिटी के अधिकारी शामिल थे।

एकेडमिक कैलेंडर में 2 माह आगे बढ़ेगा कॉलेज शिक्षा सत्र

इंदौर। उच्च शिक्षा विभाग ने नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया और एकेडमिक कैलेंडर पर काम शुरू कर दिया है। संभावना है नया सत्र इस बार 1 जुलाई के बजाय 15 सितंबर से शुरू हो सकता है। 1 अक्टूबर तक भी आगे बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार बीबीए, बीसीए, बीए-एलएलबी जैसे कोर्स की सेमेस्टर परीक्षा नवंबर-दिसंबर के बजाय जनवरी-फरवरी में होगी। वहीं बीकॉम, बीए, बीएससी जैसे यूजी कोर्स की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च के बजाय 1 मई से प्रारंभ होंगी। अतिरिक्त क्लासेस लगाकर भी कोर्स समय पर पूरा करवाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो परीक्षाएं अप्रैल में भी हो सकती हैं।

वेतन न देने पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक संबंधी अंतरिम आदेश जारी रहेगा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की अवधि का पूरा वेतन न दे पाने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश मंगलवार को आगे जारी रखा।

लॉकडाउन में मजदूरी भुगतान से छूट की आस लगाई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई में जस्टिसद्वय अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की खंडपीठ ने केंद्र से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर तत्काल कोई कदम उठाये। जस्टिस भूषण ने कहा कि इसकी तात्कालिकता को समझिए और एक सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए। दरअसल, कंपनियों के समूह ने याचिका दाखिल करके कहा कि वे लॉकडाउन अवधि का वेतन कामगारों को नहीं दे सकते, क्योंकि कामधंधा न होने से कंपनियां फटेहाल हो चुकी हैं।

एटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुनवाई में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मई को एक नई अधिसूचना जारी की है, जो 29 मार्च की अधिसूचना को निष्प्रभावी करती है। गौरतलब है कि मजदूरों के वेतन को लेकर एमएसएमई कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकने वाली कंपनियों के खिलाफ एक हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान के निर्देश

भोपाल, (एजेंसी)। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख ने संचालक तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों और आईटीआई में सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों को नियमानुसार लॉकडाउन अवधि का भी मानदेय भुगतान की कार्यवाही निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग एक हजार अतिथि विद्वान सेवाएं दे रहे हैं। निर्देशों के परिपालन में संबंधित अधिकारियों द्वारा अतिथि विद्वानों को लॉकडाउन अवधि के मानदेय भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता से शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सभी संस्थाओं को आवश्यक बजट भी आवंटित किया जा चुका है। यह निर्देश भारत सरकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी तकनीकी/शैक्षणिक संस्थाओं में सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों के संबंध में जारी किए गए हैं।

हा.से. परीक्षा की शेष परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केंन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्था करनें के निर्देश

उमरिया, (नव स्वदेश)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुल गुप्ता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2020 की शेष बची परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 09 जून 2020 से प्रारंभ होकर पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित किये जाने संबंधी निर्देश पत्र जारी किया गया है परीक्षाओं के सफल संचालन एवं संक्रमण से बचाव के लिये जिला स्तर पर व्यवस्थायें की जानी हैं। कंटेनमेंट जोन में यदि कोई परीक्षा केन्द्र निर्धारित है अथवा किसी परीक्षा केन्द्र संस्था को नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों के लिये क्वारेंटाईन सेंटर बनाया गया हो. तो ऐसे क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र जिला कलेक्टर द्वारा परिवर्तित कर मण्डल को 28 मई 2020 तक अवगत कराया जाना है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि परिवर्तित परीक्षा केन्द्र की सूचना संबंधित छात्रों को भी अनिवार्य रूप से दी जाएँ। मण्डल परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के लिये नियुक्त केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष को अपरिहार्य कारणों से जिला कलेक्टर द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में पूर्व केन्द्राध्यक्ष से नवीन नियुक्त केन्द्राध्यक्ष को गोपनीय सामग्री (प्रश्न-पत्र), परीक्षा की अन्य सामग्री एवं केन्द्र व्यय राशि का स्थानान्तरण अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र को सेनेटाईज कराया जाए एवं परीक्षा केन्द्र पर सेनेटाईजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था भी की जाए।

परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों को अपने नाक, मुंह को कपड़े से ढककर रखना अनिवार्य होगा एवं फिजिकल डिस्टेन्स नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाये। यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर फिजिकल डिस्टेन्स नियम का पालन कराने में असुविधा होने की स्थिति में उक्त केन्द्र का अनुपूरक उप केन्द्र बनाकर अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, किन्तु उक्त स्थिति में अनुपूरक, उप केन्द्र की दूरी मुख्य परीक्षा केन्द्र से अधिक नहीं होनी चाहिये। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से 28 मई .2020 तक अवगत कराने को कहा गया है। समस्त परीक्षा केन्द्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए तथा धर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी अधिकारी कर्मचारी अथवा छात्र अथवा परीक्षा कार्य में संलग्न किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान अधिक आने की स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे। किसी भी परीक्षा केन्द्र को अन्यत्र परिवर्तित किया जाता है तो उक्त केन्द्र पर संलग्न संस्थाओं के प्राचार्यों एवं संबंधित छात्रों को परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की जानकारी से अवगत कराया जाए साथ ही आवश्यकता अनुसार परिवहन की व्यवस्था भी की जा सकती है। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित थाने में रखें प्रश्न-पत्रों का भौतिक सत्यापन कराकर यह सुनिश्चित करा लिया जावे कि कि प्रश्न-पत्र पर्याप्त मात्रा में हैं. सुरक्षित है और उनकी गोपनीयता भंग नही हुई है।

परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, उक्त से संबंधित छात्रों को भी अवगत कराया जावे। परीक्षाओं के संचालन व व्यवस्था के संबंध में जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु दिनांक नियत नही की गई है के संबंध आवश्यक कार्यवाही कर 2 जून 2020 तक अनिवार्यतः प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के कारण जो छात्र एक जिले से दूसरे जिले में विस्थापित हुये उनसे 28 मई 2020 तक आनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है. ऐसे छात्रों के ऑनलाइन आवेदन नियत तिथि तक अनिवार्यतः करा दिया जावे।

एग्ज़ाम सेंटर बदलवाने का आखिरी मौका कल तक

सिटी रिपोर्टर | इंदौर माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं बोर्ड परीक्षा के ऐसे विद्यार्थी जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण दूसरे जिलों में फंस गए हैं और उसी जिले से परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें अपना एग्ज़ाम सेंटर बदलना हो तो 28 मई तक एप्लाय कर लें।25 मई से यह प्रकिया शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन किओस्क, मंडल के मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिले की समन्वयक संस्था, मंडल के संभागीय कार्यालयों के माध्यम से भी विद्यार्थियों के लिए लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

आरजीपीवी यूआईटी ने निकाले गए संविदा व्याख्याताओं को वापस रखा

तकनीकी अतिथि विद्वानों को मिलेगा लॉकडाउन अवधि का भी मानदेय

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़े अतिथि विद्वानों और संविदा व्याख्याताओं के लिए मंगलवार का दिन वाकई मंगलमय रहा। एक ओर विभाग ने लॉकडाउन अवधि में भी अतिथि विद्वानों को मानदेय देने का आदेश जारी कर दिया। वहीं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (यूआईटी) से निकाले गए 74 संविदा व्याख्याताओं को वापस ज्वाइनिंग दे दी है। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बहुत पहले ही लॉकडाउन अवधि में अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों को मानदेय जारी करने के आदेश दे दिए थे। बावजूद तकनीकी शिक्षा विभाग के 1100 अतिथि विद्वानों को मार्च माह से मानदेय नहीं मिल रहा था। इधर पांच दिन पहले आरजीपीवी यूआईटी ने 74 संविदा व्याख्याताओं को सेवा शर्त का हवाला देते हुए लॉकडाउन में बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

तकनीकी शिक्षा विभाग के 1100 अतिथि विद्वानों को मार्च माह से नहीं मिला वेतन, आर्थिक संकट झेलने को मजबूर

सोशल मीडिया पर चलाया था कैंपेन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने लॉकडाउन अवधि में मानदेय देने और नौकरी से नहीं निकाले जाने संबंधी 15 अप्रैल को ही निर्देश दे दिए थे। मानदेय नहीं मिलने और नौकरी से निकाले जाने के विरोध में अतिथियों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया था।

दो दिन में 46 अतिथि व्याख्याताओं की भी हो जाएगी वापसी

बीते पांच दिनों के अंदर आरजीपीवी ने 120 अतिथि व्याख्याताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वैसे जिम्मेदारों को एआईसीटीई की गाइडलाइन की पूरी तरह जानकारी थी, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं का आरोप अपने दामन पर न लगे इसलिए नियमानुसार कार्रवाई कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद निकाले गए 120 में से मंगलवार को सिर्फ यूआईटी आरजीपीवी के 74 अतिथि व्याख्याताओं को वापस लिया है। दो दिन में यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक के 26 और यूआईटी शहडोल के 20 अतिथि व्याख्याताओं को भी वापस बुला लिया जाएगा।

पीएस ने टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर को भेजा था सख्त रिमाइंडर

टेक्निकल एजुकेशन के प्रमुख सचिव ने डायरेक्टर को अतिथि विद्वानों के मानदेय के संबंध में 15 मई को सूचित किया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इधर पीएस के पास मानदेय नहीं मिलने की शिकायतें मिलती रही। इसके बाद 23 मई को सख्त रिमाइंडर भेजकर यह कहा गया कि ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आपको पुन: स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संपूर्ण भुगतान के बाद 26 मई तक पालन प्रतिवेदन भेजेंगे। जिसके बाद 1100 अतिथि विद्वानों को मानदेय जारी करने संबंधी आदेश मंगलवार को जारी हुआ। इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है।

बीएलएनसी लाइब्रेरी मोबाइल एप्लिकेशन करेगा लॉन्च

मध्यप्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भोपाल में शैक्षणिक पुस्तकालयों का नेटवर्क स्थापित करने को लेकर एक ऑनलाइन बैठक मंगलवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल के निदेशक अजीत खरे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की और भोपाल लाइब्रेरी नेटवर्क कंसोर्टियम (बीएलएनसी) बनाने की पहल की है। बीएलएनसी का मुख्य उद्देश्य एक सामान्य मंच प्रदान करना है जहां बीएलएनसी शैक्षणिक संस्थान सदस्य कॉपी राइट नियम और बौद्धिक संपदा अधिकारों की अनुमेय सीमा के भीतर शैक्षणिक संसाधन साझा कर सकते हैं। बीएलएनसी एक गतिशील और इंटरैक्टिव वेबसाइट विकसित करेगा जहां सभी सदस्य संस्थानों की केंद्रीय सूची उपलब्ध कराई जाएगी। बीएलएनसी एक शैक्षिक गाइड और ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की लिस्टिंग भी विकसित करेगा। जल्द ही बीएलएनसी लाइब्रेरी मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च करेगा जो सभी बीएलएनसी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा।

स्कूलों की नवीन मान्यता के लिए 10 जून तक कर सकेंगे आवेदन

रीवा। हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल की नवीन मान्यता के लिए आवेदन की तिथि में संसोधन किया गया है। पहले यह तिथि सिर्फ 30 मई तक निर्धारित थी, इसे बढ़ाकर अब 10 जून कर दिया गया है। स्कूल संचालक एमपी आनलाइन से आवेदन कर सकेंगे। नवीन और नवीनीकरण मान्यता के ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। एमपी आनलाइन पर सभी दृष्िअयों से पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र 10 जून तक अपलोड करना होगा। सभी प्रकरण से पूर्ण आवेदन पत्र के भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण के लिए प्रतिवेदन 20 जून तक संभागीय संयुक्त संचालक को भेजना होगा। 30 जून तक जेडी नवीन और नवीनीकरण मान्यता प्रकरणों पर निर्णय ले सकेंगे। 10 जुलाई तक निरस्त होने वाले आवेदक आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को आनलाइन प्रथम अपील कर सकेंगे। 20 जुलाई तक आयुक्त आनलाइन प्राप्त प्रथम अपील के निराकरण कर सकेंगे। 27 जुलाई तक द्वितीय अपीलल और उसके निराकरण के लिए 5 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है।